P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9* May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

# भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति, समस्याएँ एवं भावी पथः एक अध्ययन

**सरिता पाण्डेय**
आचार्य,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
दी0द0उ0गो0वि0वि0,
गोरखपुर, उ0प्र0, भारत

**ईश्वर चन्द्र**
शोध छात्र,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
दी0द0उ0गो0वि0वि0,
गोरखपुर,उ0प्र0, भारत

**सारांश**

शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। सभी मनुष्य जन्मजात सम्भावनाओं व विशिष्टताओं में अद्वितीय होने के साथ ही समान भी है। अतः उन सभी को आरम्भ से ही ज्ञान, कौशल व अभिवृत्तियों आदि के अधिकतम विकास का समान अवसर मिलना चाहिए उक्त कार्य में बालक के प्रारम्भिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए सभी नागरिकों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 2030 तक बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय कर रखा है। जबकि भारत में सिर्फ 12 प्रतिशत लोगों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल पाता है। जब एक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करें तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह 21वीं सदी के कौशल जैसे लेखन, संचार, आलोचनात्मक चिंतन और सहकार्यता प्राप्त करें जो उसे सुविज्ञ एंव उपयोगी नागरिक बना सके। शिक्षा हमारे देश का मुख्य आधार है। यह राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए एक साधन है। हमारे देश के लिए अच्छी खबर है कि वैश्विक विश्वविद्यालय, रोजगार क्षमता रैकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली एवं भारतीय विज्ञान संस्थान (ISC) बैंगलौर ने शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनायी है। यह सफलता हमारे संस्थानों का मनोबल बढ़ाने वाली है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है।

**मुख्य शब्द :** उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का क्रियान्वयन, भावी पथ।

**प्रस्तावना**

शिक्षा मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया है। सभी मनुष्य जन्मजात सम्भावनाओं व विशिष्टताओं में अद्वितीय होने के साथ ही समान भी है। अतः उन सभी को आरम्भ से ही ज्ञान, कौशल व अभिवृत्तियों आदि के अधिकतम विकास का समान अवसर मिलना चाहिए उक्त कार्य में बालक के प्रारम्भिक शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए सभी नागरिकों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती है। उच्च शिक्षा का अर्थ है–सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। सामान्यतः उच्च शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, विशिष्ट शिक्षा संस्थान में प्रदान की जाती है। भारत में उच्च शिक्षा के इतिहास का अध्ययन तीन कालों के अंतर्गत किया जाता है–प्राचीन काल, मध्य काल एवं आधुनिक काल, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल को समान्यतः दो उप कालों में विभाजित किया जाता है–वैद्विक काल, बौद्ध काल, परन्तु आधुनिक काल को चार उप कालों में विभाजित किया जाता है–ईसाई मिश्नरी काल, ईस्ट इंडिया कंपनी काल, ब्रिटिश शासन काल एवं स्वतंत्र काल। सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में केवल 19 विश्वविद्यालय थे परन्तु वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समस्या के विभिन्न आयाम है– शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र के साथ–साथ उच्च शिक्षा के निजीकरण, पाठय्क्रम एकरूपता, छात्रों के प्रवेश, आचार्यो की नियुक्ति, शिक्षा का गिरता स्तर, शोध पत्रों का गिरता स्तर। उक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुये उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा स्तर को बढ़ाये जाने की जरूरत है। शिक्षा हमारे देश का मुख्य आधार है यह राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए एक साधन है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के शैक्षिक क्षेत्र में अनेक समस्याओं के बाद भी भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति में काफी प्रगति हुई है। अमेरिका, चीन के बाद भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है।

**अध्ययन का उददेश्य**

1. भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति की अध्ययन करना।
2. भारतीय उच्च शिक्षा के संदर्भ में उत्पन्न शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. भारतीय उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन एवं व्याप्त समस्याओं के लिए भावी पथ के निर्धारण का अध्ययन करना।

**साहित्यावलोकन**

शिक्षा द्वारा बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास किया जाता है। उच्च शिक्षा एवं शोध किसी राष्ट्रीय विकास की प्रगति की रिढ़ होते है। इस सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ0 निरंजन कुमार द्वारा दैनिक जागरण समाचार पत्र (16 अप्रैल 2015) के सम्पादकीय ''उच्च शिक्षा का काया कल्प जरूरी'' लेख में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संख्यात्मक विकास के साथ–साथ गुणात्मक विकास हेतु यू0जी0सी0 एवं भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जाने हेतु बल दिया जिससे कि भारत वर्ष की गिनती एक उन्नत राष्ट्र के रूप में हो सके। 19 जुलाई 2016 को दैनिक जागरण में डॉ0 भरत झुनझुनवाला द्वारा प्रकाशित ''उच्च शिक्षा के भावी पथ'' में मानव संशाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेड़कर द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थाओं में अध्यापको की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर देने के वक्तव्य का स्वागत किया है। 26 सितम्बर 2016 को दैनिक जागरण में डॉ0 ए0के0 अग्रवाल द्वारा प्रकाशित ''वर्तमान में शिक्षा एवं उसका भविष्य'' लेख में इस बात पर बल दिया कि उच्च शिक्षा में सुधार करने हेतु स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षण संस्थानों में अत्यन्त आवश्यक है। फरवरी 2017 में उच्च शिक्षा की समस्याएं (राष्ट्रीय सहारा) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का यह बयान कि प्रत्येक तीन वर्षो पर उच्च शिक्षा के पाठय्क्रम में बदलाव की जरूरत है– दर्शाता है कि सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जागरूक है। 22 सितम्बर 2018 (www.franchiseindia.com)''भारत में शिक्षा की गुणवत्ता'' के लेख में इस बात का सुझाव दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिक पूंजी, बेहतर जागरूकता एवं कार्यन्वित रणनीतियों में सुधार करना अत्यन्त जरूरी है।

**भारतीय उच्च शिक्षा की स्थिति**

उच्च शिक्षा का अर्थ है– सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों में विशेष विशद तथा सूक्ष्म शिक्षा। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है। जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों, लिबरल आर्ट कालेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह शिक्षा का तृतीय स्तर है। जो ऐच्छिक होता है। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि आते है।[1]

हमारे देश में उच्च शिक्षा की शुरूआत वैदिक काल में हो चुकी थी तब उच्च शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के बाद गुरूकुलीय शिक्षा से था। उस समय इसकी अवधि सामान्यतः 12 वर्ष थी बौद्ध काल में उच्च शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा से था और इसकी अवधि भी सामान्यतः 12 वर्ष थी परन्तु इसका पाठयक्रम वैदिक कालीन उच्च शिक्षा की अपेक्षा विस्तृत था मुस्लिम काल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसमें भी प्राथमिक शिक्षा के बाद की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहां जाता था परन्तु इसकी अवधि सामान्यतः 8 वर्ष की थी तथा इसका पाठय्क्रम भी भिन्न था। भारत में आधुनिक उच्च शिक्षा का श्री गणेश यूरोपीय ईसाई मिश्नरियों द्वारा हुआ। इस देश में सर्वप्रथम पुर्तगाली ईसाई मिश्नरियों का प्रवेश हुआ। उन्होने यहां प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ गोआ, कोचीन, चाल एवं बान्द्रा में कुछ उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की। इन कालेजों में लैटिन, पुर्तगाली, व्याकरण, संगीत तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। भारत में उच्च शिक्षा का श्री गणेश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया इसने सर्वप्रथम 1781 ई0 में कलकत्ता में ''कलकत्ता मदसा'' की स्थापना की 1791 ई0 में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ''बनारस संस्कृत कालेज'' की स्थापना की तथा इसके साथ ही सन 1800 ई0 में उन्होने कलकत्ता में केवल इंग्लैण्ड की उच्च शिक्षा प्रणाली पर आधारित ''फोर्ट विलियम कालेज'' की स्थापना की।[2]

प्रथम ''भारतीय शिक्षा आयोग, 1882'' ने उच्च शिक्षा के पाठय्क्रम को और विस्तृत एवं विविध बनाने का सुझाव दिया साथ ही साथ 1917 ई0 में ''कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग'' ने विश्वविद्यालयों में कृषि, कानून, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरिंग और शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ। 1948 में भारतीय सरकार ने राधाकृष्णनन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया और उसमें सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) में उच्च शिक्षा पर लगभग 10 करोड़ रूपये खर्च किये गये सरकार ने सन् 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)'' के रूप में समुन्नत किया तथा वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गयी। जो आज भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।[3] इसके द्वारा समय–समय पर निम्न कार्य किये जाते है।

1. उच्च शिक्षा के स्तर मान बनाएं रखना।
2. उच्च शिक्षा के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना।
3. उच्च शिक्षा संस्थानों को आर्थिक अनुदान देना।
4. उच्च शिक्षा संस्थानों को परामर्श देना।
5. उच्च शिक्षा संस्थाओं का समय–समय पर मार्ग–दर्शन करना।
6. विभिन्न प्रकार के सेमिनार, वर्कशाप आदि का आयोजन करवाना।
7. विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा के पाठय्क्रम, शोधकार्य, परीक्षा आदि सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त करना।
8. नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करना।

इसी क्रम में 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन किया गया तथा साथ ही साथ कई नये विश्वविद्यालय, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, विधि एवं शिक्षक शिक्षा के स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इसी क्रम में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में शैक्षिक योजनाओं के अंतर्गत 1201 करोड़ रूपये विश्वविद्यालय शिक्षा पर व्यय किये गये। तथा दिल्ली में 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना की गयी एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE-1986) की घोषणा की गयी साथ ही साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाये गये।

भारत में उच्च शिक्षा का प्रारम्भ प्राचीन काल में हो चुका था परन्तु इसके आधुनिक स्वरूप की शुरूआत अंग्रेजी शासन काल में हुई परन्तु अंग्रेजी शासन काल में इसका विकास अत्यन्त धीमी गति से हुई स्वतंत्रता के बाद तथा हिन्दुस्तान–पाकिस्तान के बटवारे के बाद भारत क्षेत्र में केवल 19 विश्वविद्यालय 452 महाविद्यालय थे एवं इसमें पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या 2,40,000 थी स्वतंत्र होने के बाद हमने हर ख्वाइसे शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाये गये धीरे–धीरे 2004–05 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या 407, सामान्य महाविद्यालयों की संख्या 10,377 एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या 1,17,77,000 हो गयी है।[4] वर्ष 1956 से करीब 30 विश्वविद्यालयों से बढ़कर वर्तमान समय में हमारे देश के सभी राज्यों में लगभग 800 से अधिक विश्वविद्यालय एवं 40000 से अधिक कालेजों की मौजूदगी के बावजूद उच्च शिक्षा पर गुणवत्ता से जुड़े सवाल खड़े होते रहते है।[5] उ0प्र0 की बात की जाये तो कुल 29 राज्य विश्वविद्यालय एवं 06 केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सापेक्ष लगभग 5000 राजकीय सहायता प्राप्त स्ववित्त पोषित कालेज सम्बद्ध हैं 06 केन्द्रीय विश्वविद्यालय में मात्र 10 से 12 महाविद्यालय सम्बद्ध होंगे। अर्थात ज्यादातर कालेज राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं ऐसे विश्वविद्यालयों का सारा ध्यान लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा और उनके परिणाम घोषित करने में चला जाता है। पढ़ाई के अलावा शोध की स्थिति दयनीय है।[6] हमारे देश में प्रशासन एवं वित्त की दृष्टि से तीन प्रकार के विश्वविद्यालय है।

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (Central Universities)
2. राज्य विश्वविद्यालय (State Universities)
3. सम्बद्ध विश्वविद्यालय (Deemed Universities)

कार्यक्षेत्र की दृष्टि से पांच प्रकार के विश्वविद्यालय है।

1. सम्बद्ध विश्वविद्यालय (Affiliating Universities)
2. शिक्षण एवं सम्बद्धता विश्वविद्यालय (Teachings & Affiliating Universities)
3. एकात्मक विश्वविद्यालय (Unitary Universities)
4. संघात्मक विश्वविद्यालय (Federal Universities)
5. खुले विश्वविद्यालय (Open Universities)

भारत में उच्च शिक्षा के स्तरमान को बनाये रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है, तथा इसके शैक्षिक उन्नयन एवं समन्वय स्थापित करने का मुख्य उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) का है।[7]

**उच्च शिक्षा की समस्याएं**

जब देश स्वतंत्र हुआ तो उच्च शिक्षा की स्थिति बड़ी शोचनीय थी न उसके उद्देश्य स्पष्ट थे न ही पाठय्क्रम उपयोगी था विश्वविद्यालय सहित उच्च विभाग संस्थानों का ढांचा भी उपयुक्त नहीं था।[8] विश्व के श्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थाओं में भारत न केवल विकसित राष्ट्रों से काफी पीछे है। बल्कि कई विकासशील राष्ट्र भी इस दृष्टि में भारत से आगे है। भारत के पास जनसंख्या के अनुपात में उच्च शिक्षा संस्थानों की काफी कमी है। साथ ही साथ शिक्षकों, कर्मचारियों एवं उनकी आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है। इसलिए आज भी सकल नामांकन अनुपात के आने निर्धारित उद्देश्य 30 प्रतिशत से काफी पीछे राज्य विश्वविद्यालयों की तरह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के काफी पद रिक्त है। शोध पत्रों का स्तर गिर रहा है। समस्या का अन्य आयाम है। विश्वविद्यालयों एवं संस्थान के कुलपतियों, निर्देशकों और उच्चतर शिक्षा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का पिछली सप्रंग सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग विधेयक में लगभग 2000 विद्वानों की एक सूची बनाने का प्रस्ताव था। इस सूची को बनाने के लिए विशिष्ट एवं ख्यातिबद्ध लोगों का एक कोलोधियम बनाने का भी प्रावधान था।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने फरवरी 2017 में यह बयान दिया था कि तीन वर्षो पर उच्च शिक्षा के पाठय्क्रम में बदलाव की जरूरत है, दर्शाता है कि सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जागरूक है।[9] परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं है।

1. प्रशासन वित्त एवं नियंत्रण की समस्या।
2. उच्च शिक्षा के निजीकरण की समस्या।
3. शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्या।
4. शिक्षकों के प्रोन्नति की समस्या।
5. दोयम दर्जे के प्रशासन एवं शोध स्तर के गुणवत्ता की समस्या।
6. पाठ्यक्रम में एकरूपता की समस्या।
7. सकल नामांकन अनुपात की समस्या।
8. मूल्यांकन कार्य में पारदर्शिता की समस्या।
9. उच्च शिक्षा में छात्रों के प्रवेश की समस्या।
10. शिक्षा के स्तर में गिरावट की समस्या।
11. छात्र राजनीति के कारण शिक्षण कार्य में बाधा की समस्या।
12. परीक्षा पद्धति में सुधार एवं पारदर्शिता की समस्या।
13. शिक्षित बेरोजगारी की समस्या।
14. छात्र आक्रोश की समस्या।
15. तकनीकी दक्षता, कौशल की मानक स्तर पर उपलब्ध की समस्या।

**उच्च शिक्षा का भावी पथ**

उच्च शिक्षा ज्ञान, उचित वातावरण और तकनीकी दक्षता शिक्षण और विद्या प्राप्ति का समावेशित रूप है। इस प्रकार यह कौशल, व्यापार, व्यवसाय के साथ ही साथ मानसिक, नैतिक, शैक्षिक स्तर के उत्कर्ष पर केन्द्रित होता है। इन सभी समस्याओं को भुलाकर शिक्षा

के स्तर एवं उसकी गुणवत्ता की ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा स्तर को बढ़ाये जाने की जरूरत है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अधिक पूँजी, बेहतर जागरूकता और कार्यान्वित रणनीतियों में सुधार करना अत्यन्त जरूरी है। शिक्षा हमारे देश का मुख्य आधार है। यह राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए एक साधन है। भारतीय छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर वर्ष लगभग 450 अरब रूपये से ज्यादा की रकम खर्च करते है। टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइन्सेस (टिस) का 2015 का अध्ययन बताता है कि देश में उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने की जरूरत है।[10] जिससे अभूतपूर्व प्रतिस्पर्धा और अवसरों को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ बेहतर गुणवत्ता और व्यक्तिकृत शिक्षा के लिए तकनीक विकसित, शिक्षा प्रणाली के विभिन्न चरणों के बीच एकीकरण, प्रभावी व्याख्यान देने के लिए शिक्षकों को अपनी शिक्षा के साथ तकनीक को एकीकृत करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।[11] ताकि जब एक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करे तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह 21वीं सदी के कौशल, जैसे लेखन, संचार आलोचनात्मक चिंतन और सहकार्यता प्राप्त करें, जो उसे एक सुविज्ञ और उपयोगी नागरिक बना सके।

19 जुलाई 2016 में उच्च शिक्षा के भावी पथ के संदर्भ में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों की जवाबदेही स्थापित करने पर जोर दिया है। जावेड़कर के मतव्य का स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी ''स्किल इंडिया योजना'' का आधार ही उच्च शिक्षा है उच्च शिक्षा में सुधार किये बिना युवाओं को आधुनिक स्किल देना लगभग असम्भव है।[12] शिक्षा हमारे देश का मुख्य आधार है। यह राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए एक साधन है। हमारे देश के लिए अच्छी खबर है कि वैश्विक विश्वविद्यालय, रोजगार क्षमता रैकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली एवं भारतीय विज्ञान संस्थान (ISC) बैंगलौर ने शीर्ष 100 संस्थानों में जगह बनायी है। यह सफलता हमारे संस्थानों का मनोबल बढ़ाने वाली है। अर्थात भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। विगत 50 वर्षो में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुना, महाविद्यालयों में 12.5 गुना, विद्यार्थियों की संख्या में 60 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 25 गुना वृद्धि हुई है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही साथ उच्च शिक्षा अवस्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी तद्नुरूप बढ़ा है।[13]

भारत सरकार ने विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या 2030 तक बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय रखा है। जबकि भारत में सिर्फ 12 प्रतिशत लोगों को ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल पाता है। उच्च शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की गयी शिक्षा द्वारा विद्यार्थी का सामान्य और जीवन के बारे में अच्छी एवं संतुलित समझ विकसित हो जाती है। जिससे वह एक जिम्मेदार नागरिक बनकर उभरता है आज समय आ गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, यूजीसी, एआईसीटीई आदि इस बारे में दूरगामी निर्णय ले जो देश की शिक्षा प्रणाली में आर्थिक पक्षों के साथ–साथ नैतिक एवं सामाजिक दायित्वों से सम्बन्धित पहलुओं को भी समाहित करें।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

*https:/hi.m.wikipidia.org/wiki/ उच्च–शिक्षा*

*लाल रमन बिहारी–2008 शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ P.g– 441–442*

*लाल रमन बिहारी–2008 शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन शिवाजी रोड, मेरठ P.g–449–450*

*श्रीवास्तव नित्या समसमायिकी भारत एवं शिक्षा (चिताएँ एवं मुदे) शाखा एवं वर्मा अंकुर–2016प्रकाशन प्रा0लि0, आगरा, P.g–202–205*

*उच्च शिक्षा का कायाकल्प जरूरी (सम्पादकीय) डॉ0 निरंजन कुमार प्रोफेसर डी0यू0 कालेज, दैनिक जागरण (16 अप्रैल 2015)*

*वर्तमान में शिक्षा एवं उसका भविष्य (सम्पादकीय), डॉ0 ए0के0 अग्रवाल प्राचार्य हिन्दू कालेज, दिल्ली, 26 सितम्बर 2016 www.jagran.com*

*गुप्ता एस0पी0, अल्का भारतीय शिक्षा का इतिहास P.g–251–252*

*सारस्वत मालती, भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं P.g- 203–207*

*मदन मोहन, उच्च शिक्षा की समस्याएं (सम्पादकीय) राष्ट्रीय सहारा फरवरी 2017*

*www.prabhatkhabar.com/news/vishesh-alekh/ उच्च शिक्षा, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता www.franchiseindia.com 22 Sept 2018*

*शिक्षा के भावी पथ www.jagran.com (19 July 2016) डॉ0 भरत झुनझुनवाला, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ एवं भूतपूर्व प्रोफेसर, आई0आई0एम0 बैंगलुरू*

*https:/hi.m.wikipidia.org/wiki/ भारत का उच्च शिक्षा तंत्र*